उत्तराखण्ड सरकार
सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
मुख्यमंत्री आवास, न्यू कैंट रोड़, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 18 अप्रैल, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–04(04/73)

मंगलवार को सचिवालय में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार के विशेष सहयोग से आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग तथा वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक समन्वयन कार्यशाला (Coordination Conference) का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उदघाटन राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार के सलाहकार मे. जनरल वी. के. दत्ता (से. नि), सचिव आपदा प्रबन्धन अमित नेगी एवं इंसीडेन्ट रिस्पॉस सिस्टम विशेषज्ञ बी. बी. गणनायक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार के सलाहकार मे. जनरल वी. के. दत्ता (से.नि.) ने कहा कि उत्तराखण्ड पर्वतीय राज्य है, जिस कारण यह प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि की दृष्टि से भी उत्तराखण्ड अत्याधिक संवेदनशील हैं और विगत वर्ष हुयी वनाग्नि से सम्बन्धित घटनाओं से वन सम्पदा के साथ ही भारी मात्रा में वन्य जीवों पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की मॉक अभ्यास करना काफी सफल रहता है। **उल्लेखनीय है कि वनाग्नि प्रबन्धन के विशेष परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार का मॉक अभ्यास आयोजित करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है।**

सचिव आपदा प्रबन्धन अमित नेगी ने कहा कि वर्तमान में गीष्म ऋतु अपने चरम में है ऐसे में वनाग्नि सम्बन्धित घटनाओं को न्यून किये जाने के साथ ही पूर्व–तैयारियों का उच्च स्तर सुनिश्चित किये जाने हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार के विशेष सहयोग से आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग तथा वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह समन्वयन कार्यशाला (Coordination Conference) का आयोजन किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में दिनांक 06 अप्रैल, 2017 को जनपद स्तर के सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से Orientation Conference का आयोजन किया जा चुका है।

आज की इस समन्वयन कार्यशाला में जनपदीय अधिकारियों के साथ वनाग्नि के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा कर प्रायः उभर कर आने वाली समस्याओं एवं शंकाओं का निदान किया गया। साथ ही मॉक अभ्यास में वन विभाग द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) के सहयोग से मानचित्रित संसाधनों के उपयोग पर भी विचार–विमर्श किया गया। कार्यशाला में समस्त जनपदों मे आपातकालीन परिचालन केन्द्रों को सक्रिय किये जाने, रिसोर्स मोबिलाईजेशन आदि की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी।

श्री नेगी ने बताया कि मॉक अभ्यास से पूर्व 19 अप्रैल 2017 को टेबल टॉप (Table Top Exercise) अभ्यास किया जायेगा व इसमें वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त जनपदों के साथ पुनः विचार–विमर्श किया जायेगा, जिसमें सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ ही वन विभाग के सम्बन्धित अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

20 अप्रैल, 2017 को वनाग्नि सम्बन्धित मॉक अभ्यास किया जायेगा, जो कि पूर्णतः इंसीडेन्ट रिस्पॉस सिस्टम पर आधारित होगा। इस मॉक अभ्यास में राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ ही समस्त जनपदीय अधिकारी भी प्रतिभाग करेंगे। साथ ही 20 अप्रैल, 2017 को मॉक अभ्यास के बाद अपरान्ह् 3.00 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त जनपदों के साथ डी–ब्रीफिंग (De-briefing) का भी आयोजन किया जायेगा।

कार्यशाला में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार के सलाहकार मे. जनरल वी. के. दत्ता (से. नि), इंसीडेन्ट रिस्पॉस सिस्टम विशेषज्ञ श्री बी. बी. गणनायक के साथ ही आपदा प्रबन्धन, वन विभाग, पुलिस, अग्निशमन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सैन्य बल, एन.डी.आर.एफ., एस.डी.आर.एफ., भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, सूचना विभाग तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग।

देहरादून 18 अप्रैल, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–03(04/72)

अखरोट की खेती के लिये 02 मॉडल फार्म विकसित किये जायें।
इन फार्म्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित किया जाय।
अखरोट की खेती को प्रोत्साहित करने के लिये व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।
वर्ष 2017 तक राज्य को 100 प्रतिशत विद्युतिकृत कर दिया जाय।
विद्युत चोरी को रोकने के लिये विभाग द्वारा कठोर कदम उठाये जायें।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को कैम्प कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास में उद्यान एवं ऊर्जा विभागों की समीक्षा बैठक ली। उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में अखरोट की अत्याधिक सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में कागजी अखरोट को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिये 2 मॉडल फार्म विकसित किये जाएं। इन फार्म्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित किया जाए। इसमें प्रशिक्षित लोगों को जोड़ा जाए। इन फार्म्स के विकसित होने के उपरान्त अन्य स्थानों पर ऐसे फार्म विकसित किये जाने चाहिए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने वॉलनट एवं अदर फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुभव का लाभ लेते हुए इसमें किसानों को अखरोट की अच्छी प्रजातियों के कलमी पौधे उपलब्ध कराये जाएं। किसानों एवं ग्रामीणों को अखरोट की खेती के लिये प्रोत्साहित करने के लिये प्रचार–प्रसार किया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिये पानी की व्यवस्था रेन वाटर हार्वेस्टिंग से किया जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि किसानों को दी जाने वाली पौध की गुणवत्ता में कोई कमी न हो, इसके लिये विभाग को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने इसके लिये एक्ट तैयार करने की बात भी कही। अखरोट को राज्य का भविष्य बताते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि अखरोट को हमें अपनी प्राथमिकता में रखना होगा।

ऊर्जा विभाग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन ग्रामों जहाँ अभी तक विद्युत नहीं पहुंची है उन ग्रामों को वर्ष 2017 तक विद्युतिकृत करना है। इसके लिये अन्य स्रोतों का प्रयोग भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर होना है। साथ ही विद्युत चोरी को रोकने के लिये कठोर कदम ऊर्जा विभाग को उठाने होंगे। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हमें गुड गवर्नेंस का ध्यान रखना है। आम जनता को होने वाली परेशानियों को कम करते हुए ऊर्जा विभाग को कार्य करना होगा।

मुख्यमंत्री श्री रावत ने देहरादून एवं हरिद्वार में अंडरग्राउण्ड केबलिंग के लिये प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिये कि बायो ऊर्जा परियोजना के तहत सरकारी मिलों को शामिल किया जाए। माईक्रो और मिनी हाईड्रो प्रोजेक्ट्स को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया जाए। इसमें स्थानीय लोगों एवं संस्थाओं को भी जोड़ा जाए। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी, अपर मुख्य सचिव डॉ.रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री अमित नेगी, श्री उमाकांत पंवार, **वालनट एंड अदर नट फ्रूट ग्रोवर्स एसोसियेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री के.सी. पाण्डेय** सहित सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 18 अप्रैल, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–02(04/71)

अवैध खनन को पूर्णतः समाप्त किया जाय।
चारधाम यात्रा मार्गों को यात्रा शुरू होने से पहले दुरूस्त कर लिया जाय।
ऑल वेदर रोड़ के निर्माण में तीव्रता लायी जाय।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को कैम्प कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास में वित्त एवं लोक निर्माण विभागों की समीक्षा बैठक ली। राज्य की आर्थिक स्थिति पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा कि हमें आय के संसाधन बढ़ाने होंगे, इसके लिये सबसे पहले अवैध खनन को रोकना होगा। इसके लिये परिवहन, वन, पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन को मिलजुलकर कार्य करना होगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की नीति को अपनाया जाय। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद हमें राज्य के विकास को अवरूद्ध नहीं होने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री रावत ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान राज्य की सड़कों की स्थिति की जानकारी ली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चारधाम यात्रा से पहले राज्य के सभी यात्रा मार्गों को दुरूस्त कर दिया जाए। यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा एवं मैन मार्गों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने ऑल वेदर रोड के निर्माण तीव्रता लाने के भी निर्देश दिये। सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करके निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने निर्देश दिये कि हमें टारगेट बना के कार्य करना होगा।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी, प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री अमित नेगी, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकि सहित सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 18 अप्रैल, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–01(04/70)**

मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम कैम्प कार्यालय में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि आबकारी को राज्य सरकार, राजस्व का जरिया नहीं बनाना चाहती है। प्रदेश में शराब को धीरे–धीरे कम करने का प्रयास किया जाएगा। वर्तमान में शराब की दुकानें के खुलने की अवधि को घटाकर 6 घंटे करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जल्द ही शराब की दुकानें केवल दोपहर 3 बजे से सांय 9 बजे तक ही खुल सकेंगी। इससे मातृशक्ति को कुछ राहत मिलेगी। युवा पीढ़ी को शराब के दुष्प्रभाव से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। शराब को कम करने के लिए भविष्य में और भी कई निर्णय लिए जा सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि आबकारी पर प्रदेश की निर्भरता कम की जा सके। राजस्व की चोरी को रोका जाएगा और प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त भार डाले बिना अन्य स्त्रोत भी विकसित किए जाएंगे। सेल्स टैक्स में पिछले केवल तीन दिनों में ही 1 करोड़ 31 लाख रूपए की कर चोरी पकड़ी गई है। अवैध शराब में लिप्त लोगों को सजा दिलाए जाने के लिए आवश्यकता होने पर एक्ट में परिवर्तन करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध खनन को पूरी तरह से रोका जा रहा है। बहुत से क्रेशर भी जब्त किए गए हैं। अवैध खनन को रोककर खनन से इस बार 1000 करोड़ राजस्व का लक्ष्य रखा जा रहा है। अभी खनन से 285 करोड़ रूपए का वार्षिक राजस्व मिल रहा है।

एक माह के कार्यकाल के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि किसी भी सरकार के लिए एक माह का समय बहुत कम होता है। फिर भी हमने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कार्यवाही भी की है। दिसम्बर 2017 तक प्रदेश में रहने वाले सभी घरों को ऊर्जाकृत करने का हमारा दृढ़ संकल्प है। वर्ष 2019 तक 100 प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। वर्ष 2022 तक सभी को अपना आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।

प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली के बारे मे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सभी का काम करने का अपना तरीका होता है। परंतु मंजिल एक ही होती है, राज्य का सर्वांगीण विकास, संतुलित, पारदर्शी व भ्रष्टाचारमुक्त विकास। हम धीरे–धीरे परंतु ठोस रूप से व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। व्यवस्थित कार्यसंस्कृति विकसित की जा रही है। माह में दो बार केबिनेट बैठकों का समय निर्धारित करना ऐसा ही एक कदम है। जमीनों की रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। चीड़ की पत्तियों के एकत्रण को मनरेगा से जोड़ा जाएगा। अखरोट के पेड़ लगाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए चौबटिया व टिहरी में मगरा को मॉडल फार्म के तौर पर विकसित किया जाएगा। चारधाम यात्रा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। प्रत्येक श्रद्धालु सरलता के साथ दर्शन कर सके और अपने साथ अच्छी यादें ले जा सके, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के संबंध में यदि कोई व्यक्ति शपथ पत्र पर तथ्यों के साथ शिकायत करता है तो आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएंगी।

रवि बिजारनियां, सहायक निदेशक : 7055007012